Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding need to expedite construction of pending irrigation projects in Jharkhand - Laid.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सोन नदी के पानी के बँटवारे को लेकर मुख्य मंत्री बिहार, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश के बीच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 16 सितंबर 1973 को बाणसागर समझौता हुआ था । इस समझौते के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी का हिस्सा मिलना था । परंतु अब झारखंड और छतीसगढ़ अलग -अलग राज्य बन गए हैं । साथ ही गंगा बेसिन की उप नदी सोन के बेसिन में पड़ने वाली नदियों पर योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का भी निर्णय हुआ था, इसके अन्तर्गत झारखण्ड में सोन नदी की सहायक नदियों पर योजनाएं बनी थी । परंतु आज तक एक भी योजना साकार नही हो पायी ।

जल के नियंत्रण और बटवारे को लेकर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, परंतु यह बोर्ड विगत 20 साल से अधिक से कार्यरत नहीं है । बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन कि या जाए । इस पुनर्गठन में छतीसगढ़ और झारखंड राज्यों को शामिल कि या जाए ।

सोन नदी से झारखंड के गड़वा, पलामू, लातेहार और चतरा के लिए पाइप लाईन के द्वारा पानी आपूर्ति की महत्वाकांक्षी परियोजना वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई थी, परंतु यह योजना भी आज तक धरातल पर नहीं आई ।

मेरे चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिचाई योजनाएँ उत्तर कोयल जलाशय, औरंगा जलाशय योजना, अमानत बैराज, गरही, मुहाने एवं मलय आदि परियोजनायें प्रमुख हैं । इन परिजोयानाओं के अलावा, गोलाई, दुलकी, अन्नजनवा, मलय, टहले, कदवान, चाको, पीरी, सोनरे, रामघाट, नकटीनाला, घाघरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिचाई परियोजनाएं लंबित हैं ।

झारखंड की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है । जिनके लिए खेती ही रोजगार व जीवनोपार्जन का मुख्य साधन है । परंतु खेती योग्य भूमि पर कुल सिचाई का 12 प्रतिशत से भी कम के लिए संसाधन उपलब्ध है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर खेत तक पानी और हर घर जल पहुंचाने का महत्ती संकल्प लिया है । अतः मेरा आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से मांग है कि झारखंड में लंबित सिचाई योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से ठोस कदम उठाये ।